



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 28 मार्च, 2018 / 7 चैत्र, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th March, 2018

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-III, Una, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in

respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMJC-IV, Una, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in that Court.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-148/84-III.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 3 days' earned leave *w.e.f.* 12-3-2018 to 14-3-2018 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 10-3-2018 & 11-3-2018 in favour of Shri S. L. Sharma, Registrar-*cum*-Special Judge, POCSO, Shimla, H.P.

Certified that Shri S.L. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri S.L. Sharma would have continued to hold the post of Registrar-*cum*-Special Judge, POCSO, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th March, 2018

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge-*cum*-JM, Court No. II, Dehra, District Kangra, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Dehra, District Kangra, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Smt. Sheetal Sharma, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Dehra, District

Kangra, H.P. *w.e.f.* 05-03-2018 to 29-03-2018 with permission to prefix 04-03-2018 being Sunday and suffix 30-03-2018 being Gazetted holiday or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-261/03-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 12 days earned leave *w.e.f.* 24-03-2018 to 04-04-2018 with permission to prefix 23-03-2018 being local holiday in favour of Smt. Parveen Chauhan, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, District Bilaspur, H.P.

Certified that Sh. Parveen Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, District Bilaspur, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-291/06.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 20-03-2018 to 29-03-2018 with permission to suffix 30-03-2018 being Gazetted holiday in favour of Sh. Subhash Chander Bhaseen, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P.

Certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

जनजातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 अक्टूबर, 2017

संख्या टी.बी.डी.(बी)1-1/99-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय विकास विभाग में परिचर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय विकास विभाग परिचर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग में परिचर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—परिचर
2. पद (पदों) की संख्या.—01 (एक)
3. वर्गीकरण.—वर्ग- IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।
4. वेतनमान.—(I) नियमित पदधारियों के लिये वेतनमान पे बैंड : पे बैंड—1
4900-10680 / रु0 जमा 1300 रुपए ग्रेड पे।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धिया :
स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार 6200 /—रुपए प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिये आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिये ऊपरी आयु सीमा में उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों, द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) *अनिवार्य अर्हता (ए)* : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं की परीक्षा पास की हो ।

(ख) *वांछनीय अर्हता(ए)* : हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.—*आयु* : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेदन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. **भर्ती की पद्धति.**—भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता : शत प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—लागू नहीं ।

14. सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अध्वधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन जन जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में परिचर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर होना.—आयुक्त (जन जातीय विकास) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्योरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त परिचर को ₹ 6200/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 186/- की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—आयुक्त (जन जातीय विकास), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिये चयन समिति.—जैसी कि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् आयुक्त (जन जातीय विकास), हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—“II” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 6200/— प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गये वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 186/—(पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे की वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किये जाने के लिये दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0. आर0 –एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18 शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-1

1.	भर्ती और प्रोन्नति नियमों के संदर्भ में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का गुणागुण निम्न प्रकार से परिकलित किया जाएगा। विहित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ दसवीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है :- (i) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक (ii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 02 अंक (iii) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है = 2.5 अंक (iv) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्ता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक (v) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष)एन.सी.सी.में प्रमाण पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता = 01 अंक (vi) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब = 2.5 अंक (vii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला = 1.5 अंक (viii) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (ix) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक	15 अंक

परिशिष्ट-II

**परिचर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम)
के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप**

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री
निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्
प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य आयुक्त (जन जातीय विभाग) के माध्यम
से जिसे इसमें उसके पश्चात् **द्वितीय पक्षकार** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को
किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और **प्रथम पक्षकार** परिचर के रूप में संविदा
के आधार पर निम्नलिखित निबन्ध और शर्तों पर सेवा करने की सहमति दी है :-

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** परिचर के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने
वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए **द्वितीय पक्षकार** की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से
उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि **प्रथम पक्षकार** की **द्वितीय
पक्षकार** के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी
तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह
प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान
संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी ।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम ₹ 6200/- प्रतिमास होगी ।
3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का
कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी
होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक
दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश
का हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस
दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के
दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा
जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की
संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा
प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति
को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष
तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही
संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा
आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से
बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं
की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा ।

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदादात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पद तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए ।
8. संविदा, पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. TBD(A)1-1/2017, Dated July, 2017 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th October, 2017

No. TBD (B)1-1/99-L.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Attendant, Class-IV (Non-Gazetted), in the Tribal Development Department Himachal Pradesh as per Annexure “A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tribal Development Department, Attendant, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Chief Secretary (TD).

Annexure-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ATTENDANT, CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TRIBAL DEVELOPMENT , HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of Post.**—Attendant
- 2. Number of Post(s).**—01 (One)
- 3. Classification.**—Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services.
- 4. Scale of Pay.**— (I) Pay band for regular incumbents:
PB-1 Rs. 4900-10680+1300 Grade Pay.

(II) Emoluments for Contract Employees:
Rs. 6200/- as per details given in Col. 15-A.
- 5. Whether “Selection”.**—N.A.
Post or “Non-Selection” Post ;
- 6. Age for Direct Recruitment.**—Between 18 years and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on Contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *adhoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S) : Should be Matric Pass from recognized Board of School Education / institution.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S): Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s).—Age : Not applicable.

Education Qualification : Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—Not applicable.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT : (a) Under this policy the Attendant in Tribal Development will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC : The Commissioner (TD) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENT : The Attendant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 6200/- P.M . (which shall be equal to minimum of the pay band +grade Pay). An amount of Rs. 186 (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY : The Commissioner ,Tribal Department (TD) H.P will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS : Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS : As may be constituted by the concerned recruiting authority *i.e.* Commissioner Tribal Development (TD) Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT : After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS: (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 186/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual leave, Medical leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for the contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness /fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

1.	Merit of minimum educational qualification, in terms of the Recruitment & Promotion Rules, shall be calculated as under:— (Percentage of marks obtained in prescribed educational qualification to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks.	85 marks
2.	Evaluation of candidates to be made in the following manner:— (i) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be =01 Mark (ii) Land less family /family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =02 marks (iii) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members in Government /Semi Government service. =2.5 Marks (iv) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity =01 Mark (v) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions =01 Mark (vi) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time =2.5Marks (vii) Widow/divorced/destitute/singly woman =1.5Marks (viii) Single daughter/Orphan =01 Mark (ix) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi- Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5Marks	15 marks

APPENDIX-II

Form of contract/agreement to be executed between the Attendant and the Government of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ Between Sh./Smt. _____ s/o/ d/o Shri _____ r/o _____.

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal

Pradesh through Commissioner Tribal Development (TD) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Attendant on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Attendant for a period of one year commencing on day of ____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the _____ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 6200/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

 (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

 (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 14 / 2018—राज्य कर

शिमला—2, 27 मार्च, 2018

संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ(10)—14 / 2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—

- (i) नियम 45 के उप-नियम (1) में, अंत में आने वाले "जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा :

परन्तु प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दशा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा:";

- (ii) नियम 124 में,—

(क) उप-नियम (4) के पहले परन्तुक में, "परन्तु यह कि कोई भी" शब्द के स्थान पर "परन्तु कोई" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (5) के पहले परन्तुक में, "परन्तु यह कि कोई भी" शब्द के स्थान पर "परन्तु कोई" शब्द रखे जाएंगे;

- (iii) नियम 125 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"125. प्राधिकरण का सचिव—अपर आयुक्त (रक्षोपाय महानिदेशालय में कार्यरत की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी, प्राधिकरण का सचिव होगा।";

- (iv) नियम 127 के खंड (iv) के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है;

- (v) नियम 129 के उप-नियम (6) में, "स्थाई समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

- (vi) नियम 133 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।";

- (vii) नियम 134 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा किया जाएगा, अर्थात्:—

"134. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना—(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी।

- (2) यदि किसी बिंदु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न है तो उस बिंदु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।”;
- (viii) नियम 137 के पश्चात्, स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, उप-खंड ख के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“ग. नियम 128 के उप-नियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनपुट प्रत्यय कर का फायदा कीमत में अनुरूप कटौती द्वारा प्राप्तकर्ता को नहीं दिया है।”;

- (ix) नियम 138 घ के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ‘रेल द्वारा परिवहन किया गया’, ‘माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना’, ‘माल का रेल द्वारा परिवहन’ और ‘रेल द्वारा माल का संचलन’ पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है।”।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—1. मूल नियम अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन-एफ(10)-13/2017, तारीख 27 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 29 जून, 2017 को संख्या: ई.एक्स.एन-एफ(10)-13/2017, तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-14/2018 तारीख 22 मार्च, 2018 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 24 मार्च, 2018, को प्रकाशित अधिसूचना संख्या: 12/2018 तारीख 22 मार्च, 2018 द्वारा उनमें अंतिम संशोधित किया गया था।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2018, dated 27-03-/2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 14/2018-State Tax

Shimla-2, the 27th March, 2018

No. EXN-F(10)-14/2018.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018.

- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

- (i) in rule 45, in sub-rule (1), after the words, “where such goods are sent directly to a job worker”, occurring at the end, the following shall be inserted, namely:—

“, and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker:

Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal:

Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.”;

- (ii) in rule 124 –

(a) in sub-rule (4), in the first proviso, after the words “Provided that”, the letter “a” shall be inserted;

(b) in sub-rule (5), in the first proviso, after the words “Provided that”, the letter “a” shall be inserted;

- (iii) for rule 125, the following rule shall be substituted, namely:—

“125. Secretary to the Authority.—An officer not below the rank of Additional Commissioner (working in the Directorate General of Safeguards) shall be the Secretary to the Authority.”;

- (iv) in rule 127, in clause (iv), after the words “to furnish a performance report to the Council by the tenth”, the word “day” shall be inserted;

- (v) in rule 129, in sub-rule (6), for the words “as allowed by the Standing Committee”, the words “as may be allowed by the Authority” shall be substituted;

- (vi) in rule 133, after sub-rule (3), the following sub-rules may be inserted, namely:—

“(4) If the report of the Director General of Safeguards referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the Director General of Safeguards to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.”;

- (vii) for rule 134, the following rule shall be substituted, namely:—

“134. Decision to be taken by the majority.—(1) A minimum of three members of the Authority shall constitute quorum at its meetings.

(2) If the Members of the Authority differ in their opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairman shall have the second or casting vote.”;

(viii) after rule 137, in the *Explanation*, in clause (c), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“c. any other person alleging, under sub-rule (1) of rule 128, that a registered person has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.”;

(ix) after rule 138D, the following *Explanation* shall be inserted, with effect from the 1st of April, 2018, namely:—

“*Explanation.*—For the purposes of this Chapter, the expressions ‘transported by railways’, ‘transportation of goods by railways’, ‘transport of goods by rail’ and ‘movement of goods by rail’ does not include cases where leasing of parcel space by Railways takes place.”.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the official Gazette of Himachal Pradesh on 29th June, 2017, *vide* notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated 27th June, 2018 and last amended *vide* notification No. 12/2018-State Tax, dated 22nd March, 2018, published in the Official Gazette of Himachal Pradesh on 24th March, 2018 *vide* number EXN-F(10)-14/2018, dated 22nd March, 2018 .

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 15/2018—राज्य कर

शिमला—2, 27 मार्च, 2018

संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ(10)—14/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ(10)—14/2018 तारीख 22 मार्च, 2018 द्वारा तारीख 24 मार्च, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 12/2018—राज्य कर, तारीख 22 मार्च, 2018 के नियम 2 के उप-नियम (ii), खण्ड (7) के सिवाए, और नियम 2 के उप-नियम (iii), उप-नियम (iv), उप-नियम (v) उप-नियम (vi) और उप-नियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2018, dated 27-03-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 15/2018-State Tax

Shimla-2, the 27th March, 2018

No. EXN-F(10)-14/2018.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rule (ii) of rule 2 [other than clause (7)], (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of notification No. 12/2018— State Tax, dated the 22nd March, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh on 24th March, 2018 vide number EXN-F(10)-14/2018, dated 22nd March, 2018, shall come into force.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 16/2018—राज्य कर

शिमला-2, 27 मार्च, 2018

संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ(10)—14 / 2018.—आयुक्त हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं, कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात:—

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
1	2	3
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय.—प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों

के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलैक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2018 dated 27-03 - 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 16/2018-State Tax

Shimla-2, the 27th March, 2018

No. EXN-F(10)-14/2018.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
1	2	3
1.	April, 2018	20 th May, 2018
2.	May, 2018	20 th June, 2018
3.	June, 2018	20 th July, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.— Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

**HOME DEPARTMENT
(Prosecution)**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 2018

No. Home (G)B(2)-1/2013.—In continuation of notification No. Home(C)F(11)-16/89 dated 30-1-1990 and in exercise of the powers conferred upon him under section 15 of Schedule Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, The Governor, Himachal Pradesh is pleased to designate all the Deputy District Attorneys-cum-Public Prosecutors in the State of Himachal Pradesh as Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases of offences under aforesaid act in designated Special Court under the Act *ibid*.

By order,
PRABODH SAXENA,
Pr. Secretary (Home).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हि० प्र०

मुकद्दमा संख्या : 74 / NT / 2016

दिनांक पेशी : 12-4-2018

Prem Singh *alias* Raj Kumar

बनाम

Prem Chand and others

निवासीयान महाल Hardi, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

Raj Kumar *alias* Prem Singh s/o Sh. Ghungar Ram, resident of Village Ambotu, Post Office Bhuana, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं० 5, खसरा नम्बरान 30, रकबा तादादी 02-23-77 है०, महाल Hardi, तहसील बैजनाथ में भू० मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. Sh. Prem Chand s/o Sh. Raya Singh s/o Sh. Jodhu, 2. Smt. Soma wd/o Sh. Mehar Chand s/o Sh. Raya Singh, 3. Sh. Parkash Chand, 4. Meghraj ss/o Sh. Kissu s/o Sh. Tota Ram, 5. Sh. Jugal Kishor son, 6. Smt. Shakuntla Devi, 7. Smt. Radha Devi ds/o Sh. Sant Ram s/o Sh. Kissu, 8. Sh. Dulo Ram son, 9. Smt. Mangi Devi d/o Smt. Changi d/o Bhuttu, 10. Sh. Thogli son, 11. Smt Rogli daughter, 12. Smt. Devku wd/o Sh. Bhuttu s/o Sh. Chodhary, 13. Sh. Sarnu *alias* Sarvdyal s/o Sh. Ghungar Ram, 14. Sh. Santi Swroop son, 15. Sh. Bharam Swroop son, 16. Sh. Gurdyal Singh son, 17. Smt. Keshri Devi wd/o Sh. Keher Singh s/o Sh. Saran, 18. Sarwati Devi, 19. Premi Devi, 20. Bimla Devi, 21. Bhagwati Devi ds/o Sh. Saran s/o Sh. Fitha, 22. Sh. Ishru Ram s/o Sh. Shivu s/o Sh. Chamru, all are residents of Mohal Hardi, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 12-4-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-3-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 75/NT/2016

दिनांक पेशी : 12-4-2018

Prem Singh *alias* Raj Kumar

बनाम

Prem Chand and others

निवासीयान महाल Hardi, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

Raj Kumar *alias* Prem Singh s/o Sh. Ghungar Ram, resident of Village Ambotu, Post Office Bhuana, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 5, खसरा नम्बरान 30, रकबा तादादी 02-23-77 है0, महाल Hardi, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. Sh. Prem Chand s/o Sh. Raya Singh s/o Sh. Jodhu, 2. Smt. Soma wd/o Sh. Mehar Chand s/o Sh. Raya Singh, 3. Sh. Prithi Pal s/o Sh. Ami Chand s/o Sh. Khazana Ram, 4. Sh. Ravinder son, 5. Smt. Babita Devi daughter, 6. Smt. Rattani Devi wd/o Sh. Karam Chand s/o Sh. Khajana Ram, 7. Sh. Baldev Singh, 8. Sh. Ashwani Kumar, 9. Sh. Tilak Raj ss/o Sh. Megh Singh, 10. Sh. Sher Singh, 11. Sh. Karan Singh ss/o Sh. Giga Ram s/o Sh. Chodhary, 12. Sh. Vinod Kumar son, 13. Sh. Sanjay Kumar son, 14. Manorma Devi d/o Sh. Basant Singh s/o Sh. Giga Ram, 15. Smt. Jagtamba Devi w/o Sh. Jaswant Singh s/o Sh. Jogisher Singh, 16. Sh. Balwant Chand son, 17. Sh. Partap Chand son, 18. Sarestha Devi d/o Sh. Thothi Ram s/o Sh. Ranu, 19. Smt. Nirmala Devi w/o Sh. Balwant Chand s/o Sh. Thothi Ram, 20. Sh. Subhinder Kumar son, 21. Sh. Rohit Kumar son, 22. Smt. Veena Devi wd/o Sh. Shakti Chand s/o Sh. Thothi Ram, 23. Sh. Kissu s/o Sh. Tota Ram s/o Sh. Dhaknu, 24. Sh. Dulo Ram son, 25. Smt. Mangi Devi d/o Smt. Changi d/o Bhuttu, 26. Sh. Thogli son, 27. Rogli daughter, 28. Smt. Devku wd/o Sh. Bhuttu s/o Sh. Chodhary, 29. Sh. Sarnu *alias* Sarvdyal s/o Sh. Ghungar Ram, 30. Sh. Santi Swroop son, 31. Sh. Bharam Swroop son, 32. Sh. Gurdyal Singh son, 33. Smt. Keshri Devi wd/o Sh. Keher Singh s/o Sh. Saran, 34. Sarswati Devi, 35. Premi Devi, 36. Bimla Devi, 37. Bhagwati Devi ds/o Sh. Saran s/o Sh. Fitha, 38. Sh. Ishru Ram s/o Sh. Shivu s/o Sh. Chamru, all are residents of Mohal Hardi, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 12-4-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-3-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 171 / 16

श्री रोहताश पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी मटकमाजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रोहताश पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी मटकमाजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र करण कुमार की जन्म तिथि 29-01-1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् माजरा में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 29-01-1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को करण कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् माजरा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 07-04-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त करण कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-03-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 159 / 18

श्री नसीम खान पुत्र श्री बशीर मौ0, निवासी कुनजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नसीम खान पुत्र श्री बशीर मौ०, निवासी कुनजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी माता अनवरी की मृत्यु तिथि 15-05-2016 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् कुनजा मतरालियों में अपने ऊपरवर्णित माता की मृत्यु तिथि 15-05-2016 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अनवरी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् कुनजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 07-04-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अनवरी की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-03-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

अदालती इशतहार

जेर आर्डर 5 रूल 20A-21, दीवानी फौजदारी (सी० पी० सी०)

ब अदालत सब रजिस्ट्रार एवं सहायक समाहर्ता-II, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र०

मुकद्दमा उनवान :-

श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी मकान नं० 269/12, चीड़ावाली, नाहन शहर,
हि० प्र० . . प्रार्थिया।

बनाम

जनता आम

प्रत्यार्थी।

इस इशतहार से जनता आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया ने समक्ष अदालत एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसके द्वारा व वसीयत को दफा 40-41 भा० प० ऐक्ट के तहत पंजीकृत करवाना चाहती है कि श्रीमती गीता पुत्री श्री कन्हिया लाल, निवासी भूपतवाला, हरिद्वार ने अपनी भूमि जो उसे अपने गुरु श्री भगवान दास चेला-स्वामी अर्जुन दास से मिली है। जिसका खाता संख्या 0257, खसरा नं० 62/30, रकबा 0.4710 है०, खसरा नं० 65/1/1 मिन, रकबा 0.4710 है०, खसरा नं० 65/3, रकबा 0.5120 है०, खसरा नं० 65/27 रकबा 0.9940 है०, खसरा नं० 67/4, रकबा 0.1540 है०, कुल खसरा कित्ता 5, कुल रकबा 2.6020 वर्ग हैक्टेयर, स्थित भूपतवाला कलां, परगना जवालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार, अन्दर सीमा नगर पालिका समिति हरिद्वार में है, बजरिया लिखित वसीयत नामा दिनांक 21-11-2015 का उसके हक में की है।

लिहाजा इस इशतहार के द्वारा अन्दर मियाद 30 दिन उजर दायर कर सकते हैं। बसूरत दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 17-2-2018 स्थान नाहन, हि0 प्र0 को मेरे हस्ताक्षर व सील अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-पंजीपाल एवं सहायक समाहर्ता,
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह,
जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 1, 2 / 2018

तारीख पेशी : 27-04-2018

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जईया राम, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जईया राम, निवासी गनोग, ग्राम पंचायत गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्रों संजय व सुमित जिनकी जन्मतिथि क्रमशः 3-12-2005 व 16-7-2007 है जो ग्राम पंचायत गनोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-04-2018 को सुबह 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पुत्रों क्रमशः संजय व सुमित की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-03-2018 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

राजेन्द्र ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**In the Court of Vivek Sharma, H.A.S. Marriage Officer S.D.M., Nahan, District Sirmaur,
Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas Sh. Neeraj Sharma s/o Sh. Purshotam Dutt, r/o Village & P. O. Mattar, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. and Smt. Seema Devi d/o Sh. Ronki Ram, r/o Village & P. O. Mattar, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 10-02-2016, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notice are given to all concerned and General Public, to this effect if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Neeraj Sharma s/o Sh. Purshotam Dutt, r/o Village & P. O. Mattar, Tehsil Nahan, District Sirmour, H. P. and Smt. Seema Devi d/o Sh. Ronki Ram, r/o Village & P. O. Mattar, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 12th day of March, 2018.

Seal.

VIVEK SHARMA, H.A.S.
*Addl. Registrar, Under Special Marriage Act-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.*

**In the Court of Vivek Sharma, H.A.S. Marriage Officer S.D.M., Nahan, District Sirmaur,
Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas Sh. Mahinder Singh s/o Sh. Ram Kishan, r/o Village Satiwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. and Smt. Surjini Rajvanshi d/o Sh. Satish Rajvanshi, r/o Ward No. 5, Bhadarpur, Tehsil & District Bhadarpur, Nepal have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 11-04-2015 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notice are given to all concerned and General Public, to this effect if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Mahinder Singh s/o Sh. Ram Kishan, r/o Village Satiwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. and Smt. Surjini Rajvanshi d/o Sh. Satish Rajvanshi, r/o Ward No. 5, Bhadarpur, Tehsil & District Bhadarpur, Nepal they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 08th day of March, 2018.

Seal.

VIVEK SHARMA, H.A.S.
*Addl. Registrar, Under Special Marriage Act-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.*

**In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Smt. Monika Sharma d/o Shri Deep Chand Sharma, r/o H. No. 60, Ward No. 9, Devi Nagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
2. Sh. Suresh Sharma s/o Shri Raj Kumar, r/o H. No. 597, Ward No. 5 near Hariom Colony Shiv Om School Radaur Yamuna Nagar, Hry.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Whereas Smt. Monika Sharma d/o Shri Deep Chand Sharma, r/o H. No. 60, Ward No. 9, Devi Nagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Sh. Suresh Sharma s/o Shri Raj Kumar, r/o H. No. 597, Ward No. 5 near Hariom Colony Shiv Om School Radaur Yamuna Nagar, Hry. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 12-03-2018 stating therein that they have solemnized their marriage on 09-03-2018 at Geeta Bhawan Shiv Mandir Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence Notices are given to all concerned and general public to this effect on 09-03-2018 between Smt. Monika Sharma d/o Shri Deep Chand Sharma, r/o H. No. 60, Ward No. 9, Devi Nagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Sh. Suresh Sharma s/o Shri Raj Kumar, r/o H. No. 597, Ward No. 5 near Hariom Colony Shiv Om School Radaur Yamuna Nagar, Hry. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 12-03-2018.

Seal.

L.R.VERMA (HAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur.*

**In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Sh. Harpreet Shahi s/o Shri Balwant Shahi, r/o H. No. 26, Ward No. 10, Paonata Sahib, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Anu d/o Shri Varinder Khullar, r/o H. No. 30, Professor Colony Model Town Yamuna Nagar, Haryana.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Whereas Sh. Harpreet Shahi s/o Shri Balwant Shahi, r/o H. No. 26, Ward No. 10, Paonta Sahib, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Anu d/o Shri Varinder Khullar, r/o H. No. 30, Professor Colony Model Town Yamuna Nagar, Haryana have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 12-03-2018 stating therein that they have solemnized their marriage on 25-03-2012 at their residence Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 25-03-2012 between Sh. Harpreet Shahi s/o Shri Balwant Shahi, r/o H. No. 26, Ward No. 10, Paonata Sahib, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Anu d/o Shri Varinder Khullar, r/o H. No. 30, Professor Colony Model Town Yamuna Nagar, Haryana he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 12-03-2018.

Seal.

L. R. VERMA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur.

